

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त नियंत्रक,
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी।

शिक्षा अनुभाग-6 (उच्च शिक्षा)

देहरादून: दिनांक: 30 मार्च, 2017

विषय:- उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के प्रशासनिक एवं एकेडमिक भवन (द्वितीय चरण) के निर्माण में धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-UOU/Fin/2016-17/बजट/79/3707 दिनांक 19.12.2016 एवं पत्र संख्या-UOU/R/B.P./2014-16/340 दिनांक 26.12.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-486/XXIV(6)/2015-40(4)/12 दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा मुक्त विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं एकेडमिक भवन के निर्माण कार्यों हेतु रू० 427.21 लाख के आंगणनों के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में शासनादेश दिनांक 30 जून, 2015 के द्वारा रू० 100.00 लाख एवं द्वितीय किस्त के रूप में शासनादेश दिनांक 02.08.2016 के द्वारा रू० 33.33 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। इस प्रकार कुल धनराशि 133.33 लाख अवमुक्त की गयी। उक्त योजना की अवशेष धनराशि रू० 293.88 लाख के सापेक्ष तृतीय किस्त के रूप में रू० 30.00 लाख (रू० तीस लाख मात्र) की धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 एवं शासनादेश संख्या-1097/XXVII(1)/2016 दिनांक 20 सितम्बर, 2016 में दिए गए दिशा-निर्देशों एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत करते हुए आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त स्वीकृत धनराशि के देयक पर निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे।
- (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।
- (3) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जबकि गत वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।
- (4) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी ओदशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (5) व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग के निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



(6) विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाएगी एवं कोई भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा क्योंकि उससे मासिक आधार पर व्यय की भ्रामक सूचना परिलक्षित होती है। इस संबंध में समस्त वित्तीय नियमों/विनियमों/कार्यदायी संस्था के साथ सम्पादित एम0ओ0यू0 का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।

(7) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0-08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को माह की अगली 05 तिथि तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

(8) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के पैरा-162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाय तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेज दिए जाय। विभिन्न अग्रिमों का आहरण अधिकारों के प्रतिनिधायन 2010 में दी गई सीमाओं के अनुसार ही किया जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-366(P)XXVI(3)2016-17 दिनांक 27 मार्च, 2017 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से (साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत विशिष्ट अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या- प्रति-संलग्न) द्वारा निर्गत किए जा रहे हैं।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चूाल वित्तीय वर्ष 2016-17 के लेखानुदान की अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202 सामान्य शिक्षा-01-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-203-विश्वविद्यालयों को सहायता-आयोजनागत पक्ष-17-मुक्त विश्वविद्यालय-00-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान की सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या: 215/XXIV(6)/2017-40(4)/12 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
5. कोषाधिकारी, हल्द्वानी।
6. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।